(ग) क्या सरकार उपर्युक्त वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास निगम और वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संतुष्ट है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के कार्यकलापों से अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला कामगारों को लाभ होता है। इस समय के० वी० आई० सी० से लाभान्वित होने वाले कुल लाभग्राहियों में से 30.35 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

इसके अलावा, पिछड़े जिलों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी वाले जिलों के लिये के० वी० आई० सी० ने भी विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकासार्थ इस विभाग के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) कई योजनाएं चला रहा है जैसे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रबंध प्रशिक्षण, प्रधान मंत्री रोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार योजना (एस ई ई वाई यू)। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के भी लाभग्राही लोगों हेतु विशिष्ट आरक्षण हैं।

(ख) और (ग) भाग (ख) तथा (ग) के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

Dbfcmstment of Nine Psu.

1425 : SHRI CHATURANAN MISHRA :
SHRI GAYA SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to divest its equity holdings in nine important central public sector undertakings upto 49 per cent ;and

(b) if so, the names of these PSUs and the total amount of money expected to be raised through this disinvestment programme and the reasons to take such a decision ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रुग्न औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि

1426. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं की घोषणा के बावजूद देश में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो मार्च, 1991, मार्च 1992 और मार्च, 1993 में देश में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या कितनी थी, और

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान बड़े, मध्यम तथा छोटे रुग्ण उद्योगों की अलग-अलग संख्या क्या थी तथा इन उद्योगों में स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों के ऋण के रूप में पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) देश में बैंकों की सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम-उपलब्ध आंकड़े मार्च, 1992 के अंत तक के हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 1991 और मार्च, 1992 के अंत में लघु क्षेत्र तथा गैर-लघु क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या और बैंक ऋण की बकाया राशि निम्न प्रकार है :–

(राशि करोड़ रु० में)

श्रेणी	एककों की संख्या		बकाया राशि	
	मार्च, 91 के अंत में	मार्च, 92 के अंत में	मार्च, 91 के अंत में	मार्च, 92 के अंत में
रुग्ण औद्योगिक एकक	221472	245575	2792.04	3100.67
गैर-रुग्ण औद्योगिक एकक	1461	1536	5105.57	5786.55
योग	222933	246111	7897.61	8887.22

उद्योगों के लाभांश में वृद्धि

1427. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों के लाभांश की राशि में पिछले कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा वाहन उद्योग के लाभांश में वर्ष-वार तथा प्रतिशत-वार वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है इन उद्योगों द्वारा उपरोक्त वर्षों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा अपने-अपने वार्षिक साधारण बैठकों में शेयरधारकों के अनुमोदन से की जाती है और हर कम्पनी में यह अलग-अलग होता है। ऐसे लाभांशों के बारे में आंकड़ों, जो कि तुलन-पत्रों में उपलब्ध होते हैं, को एक जगह संकलित नहीं किया जाता है तथा उद्योगवार कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कई औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रही कम्पनियों द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए घोषित लाभांश की राशि में बढ़ौतरी की प्रवृत्ति रही है।

चुनिन्दा कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ कम्पनियों में गत वर्ष (1991-92) की तुलना में वर्ष 1992-93 के लिए ऊंचे दर पर लाभांश की घोषणा की है। वर्ष 1992-93 के लिए चीनी के विनिर्माण में लगी 27 कम्पनियों में से 19 ने लाभांश की घोषणा की है, और इन 19 कम्पनियों में से 10 कम्पनियों ने उच्च दरों पर लाभांश की घोषणा की है। सीमेंट के विनिर्माण में लगी 32 कम्पनियों में से 16 कम्पनियों ने वर्ष 1992-93 के लिए लाभांश की घोषणा की है तथा इन 16 कम्पनियों में से 5 कम्पनियों ने उच्च दरों पर लाभांश की घोषणा की है। आटोमोबाइल्स, हल्के वाणिज्यिक वाहनों व भारी वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण में लगी कम्पनियों के मामले में 13 कम्पनियों में से 7 ने वर्ष 1992-93 के लिए लाभांश घोषित किया है और इन 7 कम्पनियों में से 2 कम्पनियों ने उच्च दरों पर लाभांश की घोषणा की है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।